following the solemn commitments made to the Ladakh Action Committee.

I may re-affirm that the people of Ladakh want to continue to be an integral part of Jammu and Kashmir State, strengthening its solidarity and integrity—of course, as an equal partner with honour, self-respect and dignity, and not as a second class citizen.

There is a limit to everything including human endurance which has reached its limit so far as the people of Ladakh are concerned.

The six month old peaceful agitation and relay *dharna* has evoked no response from the authorities. The Ladakh Action Committee in a Resolution passed on the 11th of July, 1982, again asked the authorities for the fulfilment of their earlier demands and also for provision of minimum facilities like augmentation of drinking water supply and minimum health and sanitary requirements of the people of Leh town within seven days, failing which the Ladakh Action Committee will be forced to intensify its agitation and *dharnas* followed by hunger strike.

I may also appeal to the Government of India to intervene in the matter, issuing a directive to the authorities concerned to honour the solemn commitments made about two years back and do not allow the most sensitive border district to rise in turmoil. This may eventually lead to for reaching consequences which may not be in the national interest. Thank you.

(iii) NEED TO PROVIDE ASSISTANCE TO DROUGHT AFFECTED HILLY DISTRICTS OF U.P.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): मान्यवर, मानसून के समय पर न आने के कारण देश के कई भाग सूखे की भयंकर चपेट में हैं । उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जनपद विगत 3 वर्षों से भंयकर रूप से सूखे से प्रभावित हैं । एक तो इस क्षेत्र में फसल यू ही कम होती है सूखे के कारण मात्र 25 प्रतिशत फसल ही हो पा रही है, फलों की फसल भी ओलों से लगातार नष्ट होती जा रही है । खेतों में कूमूंला नामक फसल नाशक कीट का भयंकर प्रकोप फैला हुआ है । इस सब का कारण लगभग तीन वर्षों से समय पर वर्षा का न होना है । यहां 95 प्रतिशत खेती वर्षा पर आधारित है । ढालदार सीढ़ीनुमा खेत वर्षा का अभाव फसल नाशक कीटों का प्रकोप तथा सिंचाई साधनों का प्रायः न होने के कारण किसान भूखमरी की चपेट में है । है ।

इस स्थिति को देखते हुये प्रदेश सरकार ने स्थानीय प्रशासन की सिफारिश पर केन्द्र सरकार से इस क्षेत्र के विकास खंड़ों को सूखा पीड़ित क्षेत्र प्रोग्राम के अन्तर्गत इनका चयन करने का अनुरोध किया है । इस संदर्भ में आवश्यक अनुशंसा हेतु जो कार्यदल गाठित किया गया है उसकी बैठक में कार्यदल के एक सदस्य द्वारा इस क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुये यहां के विकास खंड़ों को भी सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये जाने की सिफारिश की । लेकिन कार्यदल के सचिव, जिनका रुख उत्तर प्रदेश के प्रति हमेशा उपेक्षापूर्ण रहा है, उनके इस कथन पर कि इस क्षेत्र के लिये कोई अन्य व्यवस्था हो जायेगी, इस क्षेत्र को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करने की अनुशंसा नहीं की गई है जब कि कोई अन्य वैकल्पिक कार्यक्रम इस क्षेत्र के लिये कृषि मंत्रालय के पास नहीं है । नया कार्यक्रम बनाने में कई वर्षों का समय लगने की सम्भावना है । इस क्षेत्र को तत्काल राहत की आवश्यकता है ।

अतः मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से प्रबल आग्रह है कि उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, उत्तर काशी तथा टिहरी जनपदों के विकास खंड़ों को तत्काल डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाए ।

(iv) NEED TO PREVENT THE USE OF INTOXICATING DRUGS BY STUDENTS.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मान्यवर, देश के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में नशे के तरन्नुम में जूझती जिन्दगी आज समाज में नजर आ रही है । स्वास्थ्य मंत्रालय की एक समिति का गठन सन् 1980 में किया गया था जिसकी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों में 39.9 प्रतिशत नशीले पदार्थ के सेवन में संलग्न हैं । इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत 20.9 प्रतिशत "पैन किलर" (दर्द दूर करने वाली गोलियां) खाने वालों का था । उसमें 12.2 प्रतिशत शराब